



Publication	Business Standard	Language	English
Edition	New Delhi	Journalist	Bureau
Date	08/06/2023	Page no	9
CCM	52.48		

## Augmenting capacity

Godowns in the cooperative sector will benefit farmers

**T**he ₹1-trillion programme approved by the Union Cabinet to create the world's largest decentralised grain storage capacity in the cooperative sector has implications that go beyond the safe upkeep of grain reserves for food security. The godowns to be built at the block level under this project are designed to serve as multifunctional centres run by the cooperatives, providing various utilitarian services to farmers. Apart from curtailing wastage of food grains and improving the economic health of the primary cooperative societies, these warehouses would also boost farm incomes. The cooperative societies would, for all practical purposes, function as grain procurement agencies, fair price shops, custom hiring centres for farm machinery, and common facilities for grading, sorting, assaying, and preliminary processing of the farm produce.

The benefits to farmers would include saving on transportation cost, as they would not have to take the produce to distant mandis, and an opportunity for realising better prices by keeping their wares in safe custody and selling them in the lean season at higher prices. The receipts issued by the warehouses for the stored stuff would serve as legally valid collateral for institutional loans. Farmers, therefore, would not have to sell their produce during the post-harvest peak marketing season when prices generally plummet to rock bottom. At the macro level, this move would help mitigate the paucity of grain storage space. At present, the available warehousing capacity, estimated at 145 million tonnes, can hold only about 47 per cent of the production. About 12 to 14 per cent of the produce gets wasted for want of proper preservation. This project would help augment the storage capacity by 70 million tonnes, increasing it to 215 million tonnes.

Interestingly, although this programme essentially fulfils the promise of setting up massive decentralised storage capacity made in the 2023-24 Budget speech, it would not require any specific budgetary allocation, or put any additional burden on the exchequer. It would actually be implemented by the Ministry of Cooperation by leveraging the funds available under various existing schemes of different ministries, notably the ministries of agriculture, food and public distribution, and food processing industries. The most noteworthy part — which also shows that the government means business in this case — is the tight time-frame specified for its execution. It stipulates setting up of a national-level coordination committee within one week of the Cabinet's approval, formulation of guidelines within 15 days, and the actual commencement of work at the cooperative society level within 45 days. A pilot project is also mooted to be taken up in 10 selected districts to gather experience that might prove useful during the actual implementation across the country.

However, while all this is welcome, the fact also is that the need for meticulous post-harvest management, including safe upkeep, is much more critical for the perishable commodities like fruit and vegetables than the cereals, which have a relatively long shelf life. The post-harvest losses for these products are as high as 25 to 30 per cent. There is, therefore, a need for a similar action plan for better care of the high-value, but spoil-prone, horticultural produce. The two initiatives together can, potentially, prove to be a game-changer for the farm sector.



Publication  
Edition  
Date  
CCM

Amar Ujala  
New Delhi  
08/06/2023  
10.22

Language  
Journalist  
Page no

Hindi  
Bureau  
12

## कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए उठाए कई कदम

नई दिल्ली। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय सहकारी समितियों के पंजीयक (सीआरसीएस) कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण की प्रगति की समीक्षा के दौरान कहा, सरकार ने कारोबारी सुगमता की दिशा में कई पहल की है। कम्प्यूटरीकरण के अंतर्गत एक सॉफ्टवेयर और पोर्टल डेवलप किया जा रहा है, जिन्हें 26 जून तक लांच करने का लक्ष्य है। सहकारिता मंत्री ने बैठक में शामिल अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीआरसीएस कार्यालय प्रतियोगिताओं के जरिये युवाओं को भी इस पोर्टल के बेहतर उपयोग और विश्लेषण में शामिल करे। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के सपनों को साकार करने के लिए जुलाई 2021 में गठित सहकारिता मंत्रालय ने सहकारिता क्षेत्र में कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए अब तक कई कदम उठाए हैं। एजेंसी



Publication  
Edition  
Date  
CCM

Dainik Jagran  
New Delhi  
08/06/2023  
12.01

Language  
Journalist  
Page no

Hindi  
Bureau  
11

## अमित शाह ने सीआरसीएस कार्यालय के कंप्यूटरीकरण की समीक्षा की

नई दिल्ली, प्रेड्र: केंद्रीय सहकारिता  
मंत्री अमित शाह ने बुधवार को  
दिल्ली स्थित सहकारी समितियों के



केंद्रीय रजिस्ट्रार  
(सीआरसीएस)  
कार्यालय के  
कंप्यूटरीकरण  
की प्रगति की  
समीक्षा की।

अमित शाह ●

बहु-राज्य

सहकारी समिति (एमएससीएस)  
अधिनियम, 2002 के क्रियान्वयन के  
की प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालने  
वाले सीआरसीएस कार्यालय का  
कंप्यूटरीकरण नई समितियों के  
पंजीकरण एवं अन्य गतिविधियों को  
सुविधाजनक बनाने के लिए किया  
जा रहा है। मंत्रालय ने एक बयान  
में कहा, कंप्यूटरीकरण का काम शुरू  
हो चुका है। साफ्टवेयर का वर्जन-  
1 मौजूदा एमएससीएस अधिनियम  
और नियमों पर आधारित है। वहीं  
वर्जन-2 के तहत एमएससीएस  
अधिनियम और नियमों में प्रस्तावित  
संशोधनों को शामिल किया जाएगा।



Publication  
Edition  
Date  
CCM

Hindustan  
New Delhi  
08/06/2023  
35.41

Language  
Journalist  
Page no

Hindi  
Bureau  
1, 12

# अमित शाह ने कहा, सौ यूनिकॉर्न स्टार्टअप बड़ी संख्या में नौकरियां दे रहे P12





# सौ यूनिकॉर्न स्टार्ट अप दे रहे नौकरियां : शाह

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने स्किल इंडिया और स्टार्ट अप के जरिये आविष्कार और आंत्रप्रिन्योर को महत्वपूर्ण बनाया है।

उन्होंने कहा कि भारत सौ यूनिकॉर्न स्टार्ट अप वाला विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जहां पिछले नौ वर्षों से ढेरों नौकरियां मिल रही हैं। शाह ने ट्विटर पर कहा कि युवा देश का भविष्य हैं और भारत ने हर क्षेत्र में युवाओं के लिए मील के पत्थर स्थापित करते हुए विकास किया है। शाह ने आगे कहा कि मोदी सरकार ने शिक्षा पद्धति में बदलाव किया और अनेक अवसर पैदा किए।

उन्होंने कहा कि सरकार ने 2017 से 2023 के बीच सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में 6.76 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत 1.21 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं और 2014 से 2019 के बीच डिजिटल अर्थव्यवस्था में 6.24



## योजना की समीक्षा की

गृह मंत्री ने केन्द्रीय सहकारी समितियों के पंजीयक के कार्यालय के कंप्यूटरीकरण की प्रगति की समीक्षा की। सीआरसीएस दफ्तर बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत काम करता है, जिनमें नई समितियों के पंजीकरण के साथ कार्य को सुगम बनाने को एक डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में कार्यालय का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है।

करोड़ नौकरियां तथा 2015 से 2018 के दौरान मुद्रा योजना के तहत 1.12 रोजगार उत्पन्न हुए हैं।



Publication  
Edition  
Date  
CCM

Rajasthan Patrika  
New Delhi  
08/06/2023  
14.13

Language  
Journalist  
Page no

Hindi  
Bureau  
2

**9400 से अधिक खुल चुके केन्द्र**

## जनऔषधि केंद्र : अब देशभर में लोगों को मिलेंगी 90% तक सस्ती दवाएं

पत्रिका न्यूज नेटवर्क  
[patrika.com](http://patrika.com)

नई दिल्ली. आम लोगों को बाजार मूल्य से 90% तक सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने वाली प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्रों का विस्तार होने जा रहा है। केंद्र सरकार 2000 नए जनऔषधि केंद्र खोलने की तैयारी में है। ये केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद कृषि ऋण समितियों

(पैक्स) में खोले जाएंगे। सहकारिता मंत्रालय ने कहा, 1,000 जन-औषधि केंद्र इस अगस्त तक बाकी दिसंबर तक खुलेंगे। देश में 9,400 अधिक केंद्र खुल चुके हैं। इन केंद्रों पर 1,800 दवाओं, 285 चिकित्सा उपकरणों की ब्रांडेड दवाओं के मुकाबले 50-90% कम कीमत पर मिलती है।

\*\*\*\*\*